Looking at Bihar special status demand sympathetically, says finance panel chief

SANTOSH SINGH
PATNA, OCTOBER 2

03/10/2018
I-E

BIHAR CHIEF Minister Nitish Kumar and his party, the Janata Dal (United), received a shot in the arm on Tuesday with 15th Finance Commission chairperson N K Singh stating that the commission is "sympathetically" considering Bihar's long-pending demand for special category status, an issue close to Nitish's heart.

Singh is leading a team of the Commission to the state to understand and assess its case for special status.

The team has already met Bihar Deputy Chief Minister and Finance Minister Sushil Kumar Modi, and is scheduled to meet the Chief Minister on Wednesday.

The five-member team began a four-day trip to Bihar on Monday.

The visit assumes significance, as Nitish often raises the demand for special category status, often seen as the Chief Minister's, and his party's, way of putting pressure on alliance partner BJP.

On Tuesday, asked by the media about the special category status demand, N K Singh, who was in Rajgir, said, "We will consider Bihar's demands sympathetically."

Singh told *The Indian Express:* "Although considering the special category status demand was not in the Finance Commission's ambit, the Commission will take a sympathetic view of the demand of grants by the state government.

Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Sushil Kumar Modi take part in 'Gandhi Padyatra' in Patna Tuesday. *PTI*

Asked whether Bihar can be granted the status, he said even earlier the Finance Commission did not deal with the issue of special category status. "We have not been asked to make any recommendation on special status. As for any special package or special concession, any revenue deficit grant can be discussed within the given framework".

On Monday, Assembly Speaker Vijay Kumar Choudhary had reiterated the state's case for "special consideration".

Incidentally, N K Singh, then a JD(U) MP, had taken up Bihar's demand for special category status with then Prime Minister Manmohan Singh.

JD(U) national spokesperson K C Tyagi told *The Indian Express:* "N K Singh knows the ins and outs of the issue. He had taken up our case as our then colleague. We still maintain that any special package will not be sufficient. We stick to our demand of special category status, as only that can ensure sufficient grants and waivers to ensure all-round growth of Bihar. Now that Singh is in the thick of things at the Finance Commission, we are very hopeful this time."

Finance Commission spokesperson Anshuman Mishra told The Indian Express: "The team has been meeting officials and the people concerned. The chairman is due to meet the CM shortly. Assembly Speaker Choudhary had spoken about special consideration. The chairman has said the Commission will consider the state's demands sympathetically."

बिहार के लिए सहानुभूति न होने का सवाल ही नहीं : एनके सिंह

Aaj 02.10.2018 PIB,Patna

पटना (आससे)। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि आयोग की अनुशंसा करते समय बिहार के लिए सहानुभूति न होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। श्री सिंह होटल मौर्या में आद्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित

राष्ट्रीय संगोष्ठी

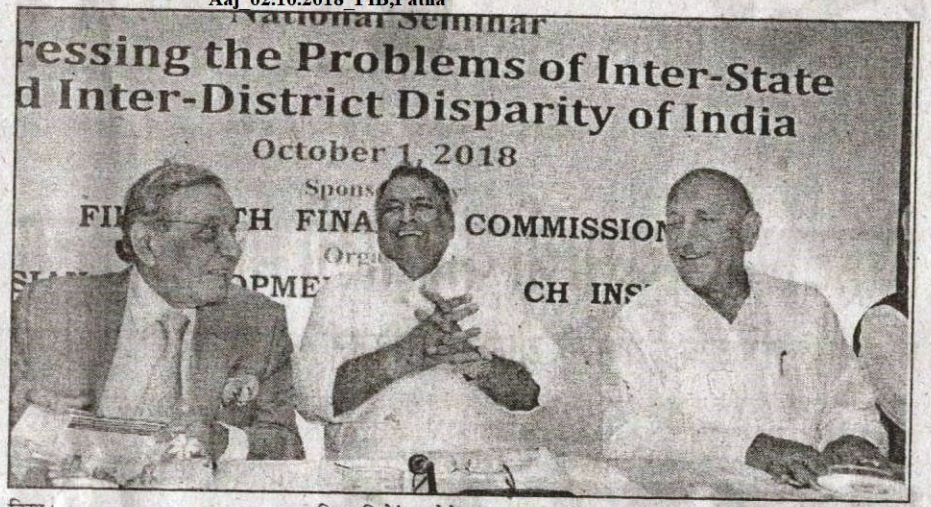

कर रहे थे। संगोष्ठी का विषय था 'भारत में राज्यों और जिलों के बीच मौजूद विषमता की समस्या का निवारण'। इस आयोजन में राज्य के शीर्ष शिक्षाविद, व्यवसायी, राजनेताओं तथा देश व राज्य सरकारक अधिकारीगण मौजूद थे।

श्री सिंह ने कहा कि जिन मुद्दों को १५वां वित्त आयोग बहुत जटिल पा रहा है, वह वस्तुत: अभीतक के सभी वित्त आयोगों के लिए बहुत जलि रहे हैं। इटली जैसे देशों के ऐतिहासिक अनुभव उन समस्याओं को समझने में बहुत उपयोगी है। उन्होंने देश में चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन करने की जरूरत पर बल दिया।

आयोजन में अतिथियों का स्वागत करते हुए आद्री के सदस्य-सचिव डा. शैबाल गुप्ता ने कहा कि ''राज्यों और जलें के बीच विकास के मामले में विषमता अकादमिक विषय भर नहीं है। यह विकास के लिए गंभीर चुनोति है और इस विषमता में की के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणें, शिक्षाविदें, प्रोफेशनल, नागरिक समाज संगठनों, मीडिया और अन्य लोगों से जैसे विभिन्न स्रोतों की प्रतिक्रिया जरूरी है।''

श्री गुप्ता के बाद बिहार सरकार के वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित किया और कहा कि ''विचार-विमर्श में पिछड़ापन के विभिन्न कारणें को चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि वे योजनाकारें को क्षेत्र आधारित विकासमूलक रणनीतियां चिह्नित करने में मदद करें। संगोष्ठी में संतुलित विकास पैटर्न को बढ़ावा देने में केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी''।

झारखंड के संसदीय कार्य तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि ''उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए हमेशा ही एक परिषद रहा है जो सातो राज्यों में विकास की दिशा में काम करता है लेकिन पूर्वी राज्य ऐसे फोकस से हमेशा वंचित रहे हैं।'' श्री राय ने यह भी कहा कि ''पूर्वी भारत में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी (अब बिहार इसका अपवाद है) के बावजूद अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के मामले में भारी कमी है। पंद्रहवां वित्त अयोग अगर इन राज्यों के लिए अनुकूल अनुशंसाएं करे तो उससे इन राज्यों को भारी मदद मिलेगी''।

बिहार विधान सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने १५वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि यह आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निहायत जरूरी होगा। बिहार के लिए 'विशेष श्रेणी' की प्रतिस्थापित (स्टेटस) की मांग पुन: उठाते हुए श्री चौधरी ने कहा कि ''अगर बिहार की भौगोलिक (जो राज्यों को यह प्रस्थिति देने का शीघ्र मापदंड है) बनावट पर विचार किया जाय, तो राज्य इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल हैं''। आद्री के निदेशक प्रभात पी. घोष ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

आज

Aaj 03.10.2018 PIB, Patna

वित्त आयोग की टीम ने किया नालंदा एवं राजगीर का दौरा

बिहारशरीफ । 15वें वित्त आयोग के बिहार दौरे के क्रम में आज 2 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने नालंदा एवं राजगीर का परिभ्रमण किया। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, सदस्य शक्तिकांत

दास, डॉ अनुप सिंह, डॉ अशोक लाहिरी, सचिव अरबिन्द मेहता, संयुक्त सचिव मुखमित सिंह भाटिया, डॉ रवि कोटा, इकोनॉमिक एडवाइजर एंटोनी सरिअक एवं अन्य पदाधिकारीगण हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुंचे। हॉकी ग्राउंड में निर्मित हेलीपैड पर जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आगवानी की। आयोग की टीम ने सर्वप्रथम नालंदा खंडहर का अवलोकन किया। वहां उपस्थित गाइड कमला सिंह ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास से सभी सदस्यों को अवगत कराया। जिसे सुनकर सभी सदस्यों ने सराहना की। नालंदा खंडहर के बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल पहुंचे। वहां उन्होंने बारिकी से उसका अवलोकन किया। अध्यक्ष ने विजिटर बुक में लिखा की इस जगह के परिभ्रमण के बगैर नालंदा का परिभ्रमण अधूरा है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। ह्वेनसांग मेमोरियल के बाद दल ने आरआईसीसी राजगीर का अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। लंच के उपरांत आयोग की टीम निर्माणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय के कैम्पस में पहुंची। वहां उन्होंने निर्माणाधीन संरचनाओं का अवलोकन किया। इसी परिसर के एक निर्माणाधीन भवन में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, फैकल्टी मेम्बर के साथ विचार-विमर्श हुआ। वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन संरचनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के गैर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

आद्री का सेमिनार • 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने दिए संकेत

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष सहायता देने पर ही होगा विचार

Dainik Bhaskar 1_02.10.2018_PIB,Patna

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठायी और कहा कि बिहार की स्थितियों पर विचार किये बगैर किसी तरह का निर्णय नाइंसाफी होगी। बिहार विशेष सहायता की पूरी पात्रता रखता है। ऐसे में बिहार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बिहार का और कितना इम्तहान होगा? चौधरी की मांग पर 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने बिहार को विशेष सहायता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की मांगों पर असहानुभूतिपूर्ण विचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार की स्थिति और परिस्थितियों से वे अच्छी तरह समझते हैं।

विजय चौधरी ने कहा भी-हम नाउम्मीद नहीं हैं। एन.के. सिंह ने कहा कि बिहार की स्थितियों को लेकर आयोग गंभीर है। बिहार इसकी पात्रता भी रखता है। हमारी कोशिश तो यही होगी कि बिहार के इस तरह से सहायता दी जाए ताकि उसे जल्द से जल्द विकसित राज्य का रूप मिल सके। सिंह, सोमवार को आद्री द्वारा यहां आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार 'एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक डिस्पेरिटी ऑफ इंडिया' विषय पर आयोजित था। उन्होंने कहा कि जहां अच्छा काम हो रहा है और जहां क्षेत्रीय असंतुलन है, दोनों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

विधानसभा स्पीकर ने प्रदेश की ओर से रखी थी विशेष दर्जा की मांग

सेमिनार में बोलते एनके सिंह। इस मौके पर स्पीकर विजय चौधरी भी मौजूद थे।

सिंह ने कहा-वित्त आयोग का संसाधन तय, फिर भी क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार राज्यों का रखेंगे ध्यान

एन.के. सिंह ने कहा कि वित्त आयोग की अपनी सीमा है। राशि निर्धारित है। उसी में खर्च करना है, बंटवारा करना है। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। बंटवारा भी इस तरह कि उसका अधिकतम उपयोग हो सके। क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार राज्यों को आगे बढ़ाया जा सके। वित्त आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। केन्द्र और राज्य के बीच राशि के बंटवारे के साथ-साथ केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की समीक्षा भी आवश्यक है। आखिर इन योजनाओं का औचित्य क्या है? इनपर खर्च होने वाली राशि का मूल्यांकन भी आवश्यक है। केन्द्रीय योजनाओं को क्या इसी रूप में छोड़ देना चाहिए? ऐसे में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

विजय चौधरी बोले-हर मानक पर बिहार विशेष दर्जा पाने का हकदार

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार का पिछड़ापन ऐतिहासिक है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी अद्भुत है। इसका 73 फीसदी इलाका बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से हर साल आधारभूत संरचना ध्वस्त होती है। बाढ़ भी हमारे कारण नहीं। नेपाल में बारिश से बिहार में तबाही होती है। पानी वहां होता है और परेशानी हमें उठानी पड़ती है। ऐसे में हमारी भौगोलिक स्थिति को नहीं देखेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। हमारी समस्याओं पर गौर नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा?

समझ नहीं आ रहा नीति आयोग का काम | पेज 6

सेमिनार • 15वें वित्त आयोग के सामने नीति आयोग के कामकाज पर विजय चौधरी व सरयू राय ने उठाए सवाल

Dainik Bhaskar_02.10.2018_PIB, Patna

समझ में नहीं आ रहा नीति आयोग का काम, कैसे हो रही है इसकी मॉनिटरिंग

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि योजना आयोग को हम अच्छी तरह समझ गए थे। पर, नीति आयोग को समझ ही नहीं पा रहे। इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह कैसे काम कर रहा है? इसके कार्यों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? आयोग द्वारा ऐसी कार्यनीति बननी चाहिए कि तय उद्देश्य पूरा हो सके। कहीं ऐसा न हो कि हम अपना मूल उद्देश्य ही भूल जाएं। वे आद्री द्वारा सोमवार को यहां आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। विषय था- 'एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक डिस्पेरिटी ऑफ इंडिया'। झारखंड के संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने भी नीति आयोग को लेकर अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसे समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है।

स्पीकर बोले- कहीं ऐसा न हो कि हम अपना मूल उद्देश्य ही भूल जाएं

आद्री की ओर से सेमिनार में उपस्थित शैबाल गुप्ता, एनके सिंह, विजय कुमार चौधरी, सरयू राय, प्रभात घोष व सुजाता चतुर्वेदी।

क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार रहा है बिहार, असली हकदार छूट न जाएं

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार ने कई सेक्टर में बेहतर कार्य किया है। महिला सशक्तीकरण में अच्छा काम हुआ है। ऊर्जा प्रक्षेत्र में बिहार मॉडल को देश लागू कर रहा है। बिहार क्षेत्रीय असंतुलन का सर्वाधिक शिकार रहा है। ऐसे में स्पेशल सहायता पाने का उसे पूरा अधिकार है। नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि जो हकदार हों, उन्हें वास्तविक सहायता मिल सके। ऐसा न हो कि असली हकदार ही छूट जाएं। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कभी खत्म नहीं हो सकेगा। चौधरी ने मध्याह्न भोजन की योजना पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयोग के विचार करना चाहिए कि क्या इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है? हमारा उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक लाना था। बच्चे आए भी। पर, हमने स्कूलों को पाठशाला की जगह भोजशाला बनाकर रख दिया है। पढ़ाई की जगह वह पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है।

विजय जी, आपने बिहार सरकार को मेमोरेंडम के लायक नहीं छोड़ा

एनके सिंह ने कहा कि विजय चौधरी जी ने इतनी अच्छी तरह से अपनी बात रखी है कि उन्होंने बिहार सरकार के मेमोरेंडम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे वे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी बातों में संपूर्ण बिहार का प्रतिनिधित्व है। मैं भी जब बिहार में प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष था और बिहार से राज्यसभा सदस्य था तो इसी तरह की बातें करता था। आज आपकी बातों में मुझे अपने शब्द नजर आ रहे हैं। विजय चौधरी व सरयू राय ने आयोग की कठिनाई बढ़ा दी है। हम इसपर गंभीरता से विचार करेंगे और इसका समाधान होगा।

क्षेत्रीय असंतुलन की नहीं पट रही खाई, नीतियां बनाने के साथ उनका कार्यान्वयन जरूरी : सरयू

झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- पूर्वी राज्यों पर फोकस जरूरी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर शुरू से बहस हो रही है। आजादी के बाद से यह विचारणीय प्रश्न है और आगे भी रहेगा। विकास व नीतियों के बावजूद खाई नहीं पट रही। हालांकि सिर्फ नीतियां ही पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार नहीं। नीतियां बनाने से अधिक महत्वपूर्ण उसका ईमानदारी से कार्यान्वयन है।

संरचनात्मक सुविधाओं की उत्तर-पूर्वी राज्यों में कमी

राय ने कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए हमेशा ही एक परिषद रही है। यह सातों राज्यों में विकास के लिए काम करती है। पर, पूर्वी राज्य ऐसे फोकस से हमेशा वंचित रहे हैं। पूर्वी भारत में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं में भारी कमी है। हालांकि अब बिहार इसका अपवाद है। 15वां वित्त आयोग अगर इन राज्यों के लिए अनुकूल अनुशंसाएं करे तो उससे इन राज्यों को भारी मदद मिलेगी।

आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने कहा कि राज्यों और जिलों के बीच विकास के मामले में विषमता एकेडमिक सबजेक्ट भर नहीं है। यह विकास के लिए गंभीर चुनौती है। इस विषमता में कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, शिक्षाविदों, प्रोफेशनल, सिविल सोसायटी संगठन, मीडिया और अन्य लोगों जैसे विभिन्न स्रोतों की प्रतिक्रिया जरूरी है।

कश्मीर के नक्शे को लेकर अधिकारी ने टोका

तकनीकी सत्र के दौरान पहले सत्र में 'रिजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया-ए मूविंग फ्रंटियर' विषय पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। इसमें कश्मीर का नक्शा गलत दिखलाया गया था। कई लोगों को इसपर आपत्ति थी। आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट से नक्शा लेने से ऐसी गलती होती है। इसपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनकी बातों पर सबने सहमति दिखाई।

पिछड़ापन के विभिन्न कारणों को चिह्नित किया जाना जरूरी : वित्त

विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने कहा कि विचार-विमर्श में पिछड़ापन के विभिन्न कारणों को चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि वे योजनाकारों को क्षेत्र आधारित विकासमूलक रणनीतियों की पहचान करने में मदद करें। संगोष्ठी में संतुलित विकास पैटर्न को बढ़ावा देने में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। आद्री के निदेशक प्रभात पी. घोष ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

वित्त आयोग के साथ बैठक

स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों ने मांगा ज्यादा अधिकार व पैसा

पटना | शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने 15वें वित्त आयोग के सामने संसाधनों की कमी का रोना रोया। सोमवार को मुख्य सचिवालय सभागार में लगभग ढाई घंटे तक चली बैठक में प्रतिनिधियों ने शहरी निकायों की खराब आर्थिक स्थिति के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को जिम्मेदार ठहराया। खुद के लिए ज्यादा अधिकार और पैसे की मांग रखी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने इस पर सकारात्मक रूप से विचार करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों को भी पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर सीधे खाते में राशि देने पर विचार किया जाएगा।

नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के प्रतिनिधियों का कहना था कि 14वें वित्त आयोग के फार्मूले की वजह से केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का अधिकतर हिस्सा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का चला जाता है। ग्राम पंचायत को तो सबसे अधिक रकम मिल जाती है। इससे दूसरी संस्थाओं का विकास बाधित हो रहा है। 15वें वित्त आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। पश्चिम चंपारण जिला परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल ने कहा कि जिला परिषद के पास संपत्तियों की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में जमीन भी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सहायता और संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग का अधिकार मिल जाए तो हमारी स्थिति सशक्त हो जाएगी। समस्तीपुर जिला परिषद की अध्यक्ष प्रेमलता ने कहा कि पार्षदों को अपने इलाके की जरूरत के हिसाब से योजना के स्वतंत्र चयन की इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही जिला परिषद को विकास योजनाओं में मरम्मत का भी अधिकार मिलना चाहिए। जहानाबाद में धरनई पंचायत के मुखिया अजय सिंह यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए 15वें वित्त आयोग को हमारे लिए पहले से अधिक राशि का प्रावधान करना चाहिए। केरल और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में ग्राम पंचायत को ग्रामसभा का अधिकार मिलना चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था को वित्त आयोग ने सराहा

पटना | 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की जम कर सराहना की है। सोमवार को पंचायत और शहरी निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। कुछ इलाकों में सुधार की अपेक्षा है जिनके बा में मैंने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से बात क है। लेकिन आमतौर पर हर तरफ शानदार तरीके से का हो रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। उन्हो कहा कि पंचायत और शहरी निकाय प्रतिनिधियों के स बातचीत सकारात्मक रही। कई उपयोगी सुझाव मिले कि पर आयोग गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। शहरी निकाय प्रतिनिधियों ने सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय इस प भी विचार किया जाएगा।

मुख्य लक्ष्य न मिस कर जाए नीति आयोग

Dainik Jagran 1_02.10.2018_PIB, Patna

राज्य ब्यूरो, पटना : एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सहयोग से सोमवार को 15वें वित्त आयोग द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने नीति आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के काम करने के तरीके से तो हम वाकिफ थे, मगर नीति आयोग को अबतक नहीं समझ पाए हैं। नीति आयोग द्वारा शब्दों की बाजीगरी हो रही है और ऐसे में कहीं मुख्य लक्ष्य मिस न कर जाए। उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के समक्ष बिहार का बहुत प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

चौधरी ने कहा कि नीति आयोग कैसे काम करता है, किसी को पता नहीं। बिहार के 38 में से 37 जिलों को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिह्नित किया गया था जिनके लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना चली। यह योजना 2015 में बंद हो गई। अब नीति आयोग ने इन पिछड़े जिलों को 'एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्ट' यानी आकांक्षी जिला का नाम दे दिया है। इन जिलों के बीच कन्वर्जेंस, कम्पीटिशन आदि की बात की जा रही है। ऐसे बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग हो रहा है, जबकि काम गांवों में होना है। किसी जिले को पिछड़े से आकांक्षी बना देने से क्या हो जाएगा? चौधरी ने मध्याह्न भोजन पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि पाठशाला, भोजशाला बन कर रह गई है। उन्होंने एनके सिंह को दो दिन पूर्व दिए उनके एक साक्षात्कार के संबंध में याद दिलाया। कहा कि आपने असम को विशेष दर्जा दिए जाने के पीछे भौगोलिक कारण बताया है। बिहार से अधिक भौगोलिक भुक्तभोगी कौन होगा। बिहार का 73 फीसद क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल में वर्षा होने से बिहार में तबाही होती है। हम नेपाल से सीधे बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 32 फीसद से बढ़ाकर 42 फीसद कर दी थी, मगर कुल राशि 13वें वित्त आयोग की तुलना में 10.9 फीसद से घटकर 9.6 फीसद हो गई। उन्होंने आग्रह किया कि इसका ध्यान रखा जाए। अन्य की तुलना में बिहार की स्थिति देखी जाए।

बिहार के प्रति सहानुभूति दिखाएगा वित्त आयोग »2

आद्री के आयोजित सेमिनार में भाग लेते वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और साथ में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी।

चौधरी ने किया आगाह

- भौगोलिक कारणों से असम को विशेष दर्जा मिल सकता, तो बिहार को क्यों नहीं
- 15वें वित्त आयोग के समक्ष असरदार अंदाज में रखा बिहार का पक्ष

वित्त आयोग को बिहार के प्रति सहानुभूति

Dainik Jagran 2 02.10.2018 PIB, Patna

बोले एनके सिंह-केंद्र एवं राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व का होगा मूल्यांकन, पंचायतों-निकायों को सीधे राशि

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं की होगी समीक्षा, अंतरजिला विषमता दूर करने का आयोग करेगा प्रयास
- आद्री के सहयोग से आयोजित हुआ अंतर्राज्यीय एवं अंतरजिला विषमता पर सेमिनार

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य के पांच दिवसीय दौरे पर 16 सदस्यीय टीम लेकर आए वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने सोमवार को आश्वस्त किया कि बिहार की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वह बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा इस संबंध में उठाए गए सवाल पर आयोग का रुख स्पष्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष के नाते यह बात उठाकर संपूर्ण बिहार की भावना से अवगत कराया है। बिहार के मामले पर बगैर सहानुभूति विचार का प्रश्न ही नहीं है।

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री) के सहयोग से सोमवार को 'अंतर्राज्यीय एवं अंतरजिला विषमता' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए एनके सिंह ने कहा कि मैं खुद बिहार राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष एवं फिर राज्यसभा सदस्य की हैसियत से बिहार की समस्याओं को उठाता रहा हूं। मेरी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, भले ही मेरी क्षमता बदली है। सेमिनार की अध्यक्षता विजय कुमार चौधरी कर रहे थे, जबकि झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय विशिष्ट वक्ता के रूप में मौजूद थे। बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण

सेमिनार में अधिकारियों के साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह

उत्पन्न समस्याओं एवं आजादी के बाद से अबतक पिछड़ेपन पर विस्तार से चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी को कोट किया-'आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, इसलिए आप अपने भूगोल को बदल नहीं सकते।' पूर्व प्रधानमंत्री का बयान पाकिस्तान के संदर्भ में आया था। एनके सिंह ने कहा कि राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसका उपयोग किस प्रकार हुआ। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य, दोनों ही सरकारों के उत्तरदायित्व की समीक्षा करेगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर गैरउपयोगी योजनाओं को बंद करेगा। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कुछ काम किया था, मगर अभी और समीक्षा करनी होगी।

यूएलबी ने कहा-15वां वित्त आयोग जमीन खरीदने के लिए भी दे राशि

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार दौरे पर आए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का शहरी नगर निकायों (यूएलबी) के नुमाइंदों ने सोमवार को तीन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया। मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोग से रूबरू यूएलबी के नुमाइंदों ने कहा कि यूएलबी के चहुंमुखी विकास के लिए 14वें वित्त आयोग से ज्यादा राशि मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही कुछ नए मद में राशि देने का प्रावधान किया जाए। इसमें मुख्य रूप से जमीन खरीदने के लिए और पुरानी योजनाओं की रख-रखाव के लिए राशि देने के अलावा और अधिक अधिकार देने यानी (स्वायतता) देने की मांग रखी। यूएलबी के नुमाइंदों ने बताया कि जमीन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से पार्किंग, वेडिंग जोन और बस स्टैंड आदि सुविधा विकसित करने में समस्याएं आ रही है। बिजली की लाइन अंडर ग्राउंड करने के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग रखी। कहा कि आयोग सीधे नगर निकायों राशि मुहैया कराने का प्रावधान सुनिश्चित करे।

किस-किस यूएलबी के नुमाइंदे हुए रूबरू

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से पटना, बेगूसराय और कटिहार नगर निगम के महापौर और उप महापौर रूबरू हुए। इसी तरह समस्तीपुर, औरंगाबाद, मोतिहारी, खगड़िया और किशनगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद ने अपनी-अपनी मांगे रखी, जबकि बोधगया, जयनगर, रामनगर और लालगंज नगर पंचायत के अध्यक्षों ने आयोग से और स्वायतता देने की मांग की।

कौन-कौन हुए शामिल

नगर निकायों के नुमाइंदों की बैठक में वित्त आयोग के समक्ष मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त, वित्त विभाग की प्रधान सचिव के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद मौजूद थे।

नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में योग की भी होगी पढ़ाई

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : मंगलवार को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने टीम के साथ नालंदा का भ्रमण किया। प्राचीन नालंदा विवि के अवशेष, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल और राजगीर की वादियों के साथ ही यूनीवर्सिटी ऑफ नालंदा का अवलोकन किया। उन्होंने नालंदा अंतरराष्ट्रीय विवि की कुलपति सुनयना सिंह से पूर्व निर्धारित बैठक नहीं की, लेकिन, उनका पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देखा और 3.30 बजे के करीब पटना के लिए रवाना हो गए। एनके सिंह अंतरराष्ट्रीय विवि की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं। इस हैसियत से उन्होंने विवि भवन निर्माण से लेकर पाठ्यक्रमों की विस्तार से जानकारी ली। बाद में वित्त आयोग के मीडिया और कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर अंशुमन मिश्रा ने बताया कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के ही पैटर्न भर अंतरराष्ट्रीय नालंदा विवि को विकसित किया जा रहा है। इस साल विवि को कुल स्वीकृत राशि 1100 करोड़ में से 300 करोड़ रुपए शीघ्र ही जारी किए जाएंगे ताकि भवन निर्माण को गति मिल सके। यहां पढ़ाए जाने वाले विषयों में गणित और दर्शनशास्त्र के अलावा योग विज्ञान का भी कोर्स जोड़ा गया है।

Dainik Jagran_03.10.2018_PIB, Patna

नालंदा आकर लगा-बदल रहा है बिहार

एनके सिंह बोले

राजगीर (नालंदा) | का.सं./नि.सं.

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ नालंदा भ्रमण किया। नालंदा महाविहार के अवशेष, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल व राजगीर की वादियों के साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का अवलोकन किया। यहां के विकास से गदगद श्री सिंह ने कहा-नालंदा आकर लगा कि सचमुच बिहार बदल रहा है।

टीम के अन्य सदस्यों से अपनी जानकारी बांटते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनाने की योजना है। रणनीति बना ली गयी है। कई मामलों में तो उस पर काम भी शुरू कर दिये गये हैं। अब तो विक्रमशिला

नालंदा खंडहर का मंगलवार को अवलोकन करते एनके सिंह व वित्त आयोग के सदस्य।

विश्वविद्यालय के भी पुनर्जागरण की बात उठने लगी है।

भ्रमण के दौरान नालंदा विवि की कुलपति डॉ. सुनैना सिंह ने यूनिवर्सिटी के विकास की बनी रणनीति का प्रेजेंटेशन दिखाया। कहा गया कि यहां गणित और दर्शनशास्त्र के अलावा योग विज्ञान के भी स्कूल खुलेंगे। वर्ष 2019 से यहां तमाम स्कूलों में पीएचडी व शोध कार्य भी शुरू किये जाएंगे। आयोग के डिप्टी डायरेक्टर ने बता[illegible] कि करार के मुताबिक हर साल [illegible] द्यालय प्रशासन को 300 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। 17 मुख्य बिल्डिंग बननी है। इसके 40 फीसदी काम [illegible] चुके हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भव्य [illegible] स्तकालय बनाने का काम शुरू हो चु[illegible] यह 24 घंटे खुले रहेंगे।

Hindustan 2_03.10.2018_PIB, Patna

Hope NU classes begin from own campus in '19: NK Singh

Arun Kumar
htpatna@hindustantimes.com

PATNA: All the members of the 15th Finance Commission, headed by former Rajya Sabha member NK Singh, on Tuesday visited upcoming Nalanda University campus as well as the ruins of the ancient Nalanda during their visit.

Singh, who is also on the governing board (GB) of NU, said that he would look forward to see classes being conducted in the new campus early next year. At present, first phase construction on the sprawling campus is on.

Former President Pranab Mukhejee had laid the foundation stone of the campus on August 27, 2016.

The members of the Finance Commission team included former revenue secretary Shaktikanta Das, Prof Anoop Singh from Georgetown University and Dr Ashok Lahiri, former economic advisor to government of India. They planted saplings to mark the occasion in the new campus.

NU vice chancellor Prof Sunaina Singh made a presentation before the Finance Commission

N K Singh

members, presenting the details of campus development plan, which she hoped should be completed by 2020. "Five buildings are coming up to house the administration and academic blocks by early next year to enable shifting of the campus," she said.

She also dwelt on the NU journey starting 2014 with just 12 students to over 300 intake in the present academic session, with students from different countries. "Four research centres will be established and Ph D programmes will commence in 2019, while we plan to have four more schools to the existing three by 2020. The university is also supporting locals by employing them in various capacities," she added.

The government of India had earlier approved an expenditure of Rs 2,727.10 crore for the period 2010-11 to 2021-22 in order to meet the university budgetary requirements during its establishment phase.

NK Singh was happy to note that an additional 100 acres would be allotted by the state government for commercial use to generate funds for the university. He also appreciated the efforts of Bihar CM Nitish Kumar and his government machinery for the iconic university.

Hindustan Times_03.10.2018_PIB, Patna

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा

बिहार को विशेष सहायता देने पर गंभीरता से विचार

पटना. बिहार के चार दिवसीय दौरे पर 15वें वित्त आयोग की टीम आयी हुई है. आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए इसकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा. विकसित राज्य का दर्जा बिहार को कितनी जल्दी मिल सके, इसके लिए हर तरह का सहयोग दिया जायेगा. बिहार से जुड़ी तमाम परिस्थितियों और आयामों को ध्यान में रखते हुए राज्य को विशेष तौर पर मदद मुहैया करायी जायेगी. एनके सिंह सोमवार को यहां एक निजी होटल में 'भारत में मौजूद अंतर राज्य और अंतर जिला विषमता' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वित्त आयोग बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मुहैया कराने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा. इससे पहले अपने संबोधन में विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार हर दृष्टिकोण

● बाकी पेज 17 पर

विशेष दर्जे के लिए फिट है बिहार : चौधरी -पेज 10

Prabhat Khabar 1_
02.10.2018_PIB, Patna

बिहार को विशेष...

से विशेष सहायता का हकदार है. इस पर आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करे. इसके जवाब में एनके सिंह ने कहा कि बिहार की मांग पर असहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर विशेष नीति तैयार करके इसका सटीक प्रयोग करना होगा, ताकि अंतर जिला विषमता (इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी) को कम किया जा सके. अंतर जिला विषमता महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में भी काफी बड़ी है. वहां तो अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि विकास कैसे और किस तरह से हो रहा है. विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे जिलों की विकास दर देश में सबसे कम है. ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बिहार की कठिनाइयों और सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा. केंद्र के पास जितनी राशि मौजूद है, उसकी जानकारी सभी को है. इसका ध्यान रखते हुए ही राशि का बंटवारा किया जायेगा. सफलता को कैसे प्रोत्साहित करना है, कैसे विकास करना है, इसी समन्वय की तलाश करने के लिए वित्त आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आयी हुई है. एनके सिंह ने कहा कि राज्य को आर्थिक सहायता वर्टिकल (रैखिक) और हॉरिजेंटल (क्षैतिज) दोनों तरीके से दी जायेगी. आर्थिक स्रोतों से प्राप्त राशि का बंटवारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से होगा. वर्टिकल बंटवारे में केंद्र और राज्य के बीच संगृहीत टैक्स का समानुपातिक तरीके से विभाजन किया जायेगा. वहीं, हॉरिजेंटल बंटवारे में राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, मौद्रिक या वित्तीय प्रदर्शन, वन आवरण समेत अन्य प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त या विशेष राशि का प्रावधान किया जायेगा. बिहार की जनसंख्या के लिए 2011 को आधार वर्ष माना गया है. इससे बिहार को फायदा होगा. केंद्रीय टैक्स शेयर में राज्य की हिस्सेदारी इन दोनों आधारों पर बढ़ने की संभावना है. बिहार की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता मुहैया करायी जायेगी.

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रेशनलाइजेशन की जरूरत : एनके सिंह ने कहा कि विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही इनका सही मायने में उपयोग करने के लिए सही नीति तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के खर्च का सही मूल्यांकन होना चाहिए. किसी योजना में खर्च हुए रुपये के सही उपयोग की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार का है. राज्यों में कितनी संख्या में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) चलती हैं, इनमें से कितनी योजनाएं सही से चल रही हैं, इनमें खर्च होने वाली राशि का मूल्यांकन करने की जरूरत है. बड़ी संख्या में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं का रेशनलाइजेशन करने की जरूर है, ताकि इनकी संख्या को कम किया जा सके. इसके लिए शिवराज कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट का कोई खास असर नहीं हुआ. सीएसएस की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है.

सेमिनार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी बोले

Prabhat Khabar-3_02.10.2018_PIB,Patna

विशेष राज्य के दर्जे के लिए फिट है बिहार

संवाददाता ▷ पटना

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे और विशेष सहायता के लिए हर तरह से फिट है. हर दृष्टिकोण से बिहार विशेष सहायता का हकदार है. उन्होंने पूरजोर तरीके से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से कहा कि बिहार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें. तभी बिहार के साथ न्याय होगा. इस बार तो आयोग के अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, जो बिहार को अच्छे से जानते हैं. बावजूद इसके कहीं बिहार विशेष राज्य के दर्जे प्राप्त करने से वंचित न रह जाये. वह आद्री की तरफ से एक निजी होटल में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार विशेष दर्जे के लिए तय तमाम मानकों में हर तरह से फिट बैठता है. चाहे वह भौगोलिक विषमता की बात हो या अंतर जिला या अंतर राज्य विषमता की, हर आयामों पर बिहार इसके लिए पूरी तरह से फिट है. यहां का 73 फीसदी भूभाग बाढ़ से ग्रसित रहता है. क्षेत्रीय विषमता से जुड़े मामलों का अध्ययन करने के लिए बिहार सबसे उपर्युक्त स्थान है. उन्होंने कहा कि बिहार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद बिजली समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर मॉडल स्थापित किया है. महिला सशक्तीकरण में भी बिहार नजीर है. तमाम कमी के बाद भी बेहतर ग्रोथ हासिल किया गया है. अब राज्य का कितना इम्तिहान लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, इससे लोग पूरी तरह से परिचित थे. इसके स्थान पर वित्त आयोग आ गया है. बीआरजीएफ (बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड) के स्थान पर एस्पायरेशनल (आकांक्षी) डिस्ट्रिक्ट आ गये हैं. इस तरह से कई नये शब्दों का मायाजाल इन दिनों फैल रहा है. कहीं इन भारी-भरकम शब्दों के चक्कर में वास्तविक टारगेट ही नहीं छूट जाये. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में प्रत्येक साल नेपाल से पानी आता है और इससे तबाही होती है. इसमें बिहार की गलती नहीं है. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां की सरकार से इस मसले पर कभी बात नहीं हो पायी. इन बातों पर गौर किये बिना विकास संभव नहीं है.

विधानसभा अध्यक्ष ने 15वें वित्त आयोग की टीम के सामने रखी बिहार को खास तवज्जो देने की मांग

झारखंड के मंत्री सरयू राय ने कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा दरकिनार कर विकास के बारे में सोचें सभी पार्टियां

कार्यक्रम में शैबाल गुप्ता, एनके सिंह, विजय कुमार चौधरी व सरयू राय.

विषमता के लिए सिर्फ नीति ही नहीं, राजनीति भी दोषी

झारखंड के संसदीय कार्य सह खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि अंतर राज्य और अंतर जिला विषमता के लिए सिर्फ नीति ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राजनीतिक विद्वेष भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है. विषमता से जुड़ा यह विषय नया नहीं है, जैसी स्थिति 40 साल पहले थी, वही स्थिति आज भी है. क्षेत्रीय विषमता के गैप या अंतर को अब तक पाटा नहीं जा सका है. योजनाएं या वित्त आयोग की जो भी अनुशंसाएं होती है, उनका क्रियान्वयन जमीन पर होना चाहिए. बिहार-झारखंड जैसे राज्य अपने हिस्से के संसाधनों का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाये है. इन राज्यों में आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं होने की वजह से संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाया है. नीतियों के क्रियान्वयन में कमी के कारण सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पूरे संसाधनों का 65 से 70 फीसदी हिस्सा मौजूद है, लेकिन उपयोग यहां नहीं हो पा रहा है. विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर करने की जरूरत है. इन राज्यों के विकास के लिए अलग से विंग बने.

भूमंडलीकरण का प्रभाव भी समाज के विकास पर पड़ा है : शैबाल गुप्ता

कार्यक्रम के स्वागत संबोधन में आद्री के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने कहा कि बिहार जैसे राज्यों के लिए इस सेमिनार का विषय बेहद मौजू है. भूमंडलीकरण का प्रभाव भी समाज के विकास पर पड़ा है. वित्त विभाग की प्रदान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने कहा कि देश में आर्थिक विकास की लंबी अवधारणा रही है. समय और जरूरत के हिसाब से योजनाएं चलायीं और बंद की जाती है. बीआरजीएफ को 2007 में शुरू करके 2015 में बंद कर दिया गया. वर्तमान वित्त आयोग पर तमाम समस्याओं और आर्थिक विसंगति को दूर करने की जिम्मेदारी है. पिछड़ेपन के सही कारणों का पता लगाकर इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए टिकाऊ प्लान की जरूरत है.

बिहार ने पंचायती राज व्यवस्था को किया मजबूत : एनके सिंह

पटना. 15वें वित्त आयोग की टीम ने सोमवार की दोपहर में सभी नगर निकायों और पंचायत राज के चुनिंदा जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया. मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस विशेष बैठक में आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जबर्दस्त तरीके से काम किया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर तरफ काम हो रहा है. पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कई साहसिक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार ने किये हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सुधार करने की गुंजाइश है. त्रिस्तरीय पंचायती राज की तर्ज पर ही नगर निकायों को भी सीधे राशि भेजने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जायेगा. निकायों को अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र ने कहा कि जिला पंचायत और पंचायत समिति को वित्त आयोग के सीधे दायरे में लाया जाये. जहानाबाद जिले के धरनई के मुखिया अजय यादव ने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ग्राम पंचायत को अधिकार मिले. समस्तीपुर की जिला अध्यक्ष प्रेमलता ने कहा कि योजना के चयन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए.

Prabhat Khabar 4 02.10.2018 PIB,Patna

कवायद ● **15वें वित्त आयोग की टीम राज्य की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने इन दिनों बिहार के दौरे पर आयी हुई है**

Prabhat Khabar 03.10.2018 PIB, Patna

वित्त आयोग विभागों से मांग रहा है कई सवालों के जवाब

संवाददाता ▷ पटना

सरकार और 12 पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक

इन दिनों 15वें वित्त आयोग की टीम राज्य की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने बिहार के दौरे पर आयी हुई है. टीम की पहली बैठक सभी नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज जन प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी है. इसके बाद यह सिलसिला दो दिनों (3 और 4 अक्तूबर) और जारी रहेगा. इस दौरान आयोग ने राज्य सरकार से कई तरह के प्रश्नों के उत्तर भी मांगे हैं, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति समेत अन्य पहलुओं की समीक्षा होगी. वित्त आयोग ने पूछा है कि राज्य में कितने लोक सेवा उपक्रम (पीएसयू) हैं, इनकी सटीक संख्या कितनी है. इनमें से कितने पीएसयू वर्तमान में काम कर रहे हैं. इनकी मौजूदा हालत क्या है. इनके पास कितने की जमीन है और इन परिसंपत्तियों की वर्तमान में बाजार मूल्य कितना है. इसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है. इस सवाल पर इस बार वित्त आयोग का फोकस सबसे ज्यादा है. इसके अलावा आयोग ने पूछा है कि राज्य का पिछले पांच साल का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है. राज्य की विकास दर कितनी रही है, इसकी मौजूदा स्थिति क्या है. पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य की विकास दर देश में सबसे ज्यादा रही, इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं. इस तरह के तमाम मसलों पर विस्तार से डाटा के साथ रिपोर्ट तैयार करके जमा करने में वित्त विभाग जुटा हुआ है. राज्य में अभी पीएसयू की संख्या करीब 74 है, जिसमें 44 पीएसयू ही कार्यरत हैं. वित्त विभाग ने सभी पीएसयू के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है. बंद पड़े पीएसयू के पास मौजूद पूरी संपत्ति का ब्योरा और इनका मौजूदा बाजार दर समेत पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा वित्त विभाग अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर जुटाने और उन्हें मुहैया कराने में भी लगा हुआ है. इस वजह से छुट्टी के दिन भी विभाग बिना बंद काम में जुटा हुआ था.

वित्त आयोग की टीम का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 3 अक्तूबर को है. इस दिन पूरे राज्य सरकार के अलावा 12 पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक होगी. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में होने वाली सभी बैठकों में सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य सरकार के सभी मंत्री और तमाम उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी. इस दौरान मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का भाषण भी होगा. इसी क्रम में आयोग को ज्ञापन सौंपा जायेगा.

साथ ही वित्त विभाग की तरफ से आयोग के समक्ष पूरे मसौदे की प्रस्तुति होगी, जिसमें राज्य की तरफ से 15वें वित्त आयोग से आने वाले पांच वर्षों में मांगी जाने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता के अलावा अन्य प्रमुख बातों का विस्तार से उल्लेख किया जायेगा. इसके बाद दोपहर को 12 अलग-अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक होगी.

बिहार अतिरिक्त सहायता पर देगा ज्यादा फोकस

15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार जो ज्ञापन सौंपेगी, उसमें आगामी पांच वर्षों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग होगी. बिहार केंद्रीय टैक्स पुल में हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है और इसे मौजूदा जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर फिक्स करवाना चाहता है. विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है, तो विशेष आर्थिक सहायता की मांग होगी. इसके तहत पांच साल में करीब चार लाख करोड़ रुपये की सहायता केंद्र से मिलने की उम्मीद रखी जायेगी. क्षेत्रीय विषमता और बंद हुए बीआरजीएफ के आधार पर क्षतिपूर्ती करते हुए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की जायेगी.

वित्त आयोग की टीम ने किया प्राचीन नालंदा विवि का भ्रमण

Sanmarg_03.10.2018_PIB,Patna

प्राचीन नालंदा विवि का भ्रमण बगैर नालंदा भ्रमण अधूरा : एन के सिंह

बिहारशरीफ। 15वें वित्त आयोग की टीम अपने चार दिवसीय बिहार दौरे के दौरान आज नालंदा पहुंची। आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग के सदस्य नालंदा पहुंचे। हवाई मार्ग से टीम के सदस्य राजगीर पहुंचे जहां नालंदा के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने टीम के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात टीम के सभी सदस्य राजगीर में कुछ देर विश्राम के बाद सड़क मार्ग से नालंदा पहुंचे जहां सर्वप्रथम वर्ल्ड हेरिटेज साईट में शामिल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण के दौरान टीम के सदस्य काफी खुश हुये। सात सौ सालों तक अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र रहा इस विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। भ्रमण के दौरान इस स्थल को देख आयोग के सभी सदस्य अभिभूत हो गये और इस स्थल पर पहुंच कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने विजिटर बुक में लिखा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण बगैर नालंदा का भ्रमण अधूरा है। सदस्यों द्वारा करीब एक घंटे तक इस स्थल का भ्रमण किया गया। तपती गर्मी के बावजूद इस स्थल को देखने और जानने की जिज्ञासा देखते बन रही थी। चार दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे टीम के सदस्यों का आज नालंदा का दौरा है। नालंदा भ्रमण के दौरान हेवनसांग मेमोरियल हॉल, वेणुवन, निमार्णाधीन अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय भी गये। तत्पश्चात सभी लोग पटना के लिए रवाना हो गये।

Singh kudos for Nalanda VC

Telegraph 03.10.2018 PIB, Patna

ROSHAN KUMAR

Patna: N.K. Singh, the chairman of the 15th Finance Commission, on Tuesday appreciated the work being carried out by the Nalanda University administration in giving pace to the construction work of the new campus.

Singh also praised Nalanda University vice-chancellor Sunaina Singh for paying keen interest in the construction of new campus. On his daylong visit to Nalanda University, he also visited the site where construction work is in progress.

A member of the Nalanda University governing board, Singh, said: "Going by the pace of the construction work, I appreciate the steps taken by the university administration along with efforts made by chief minister Nitish Kumar and the state government in providing necessary assistance."

The campus is coming up on 455 acres, which is 2.5km away from Rajgir bus stand and 110km southeast of Patna. Sources said the construction work on the new campus gained momentum after Sunaina Singh assumed charge as the vice-chancellor.

The foundation stone for the new campus of the Nalanda University was laid in March 2017, while the construction work commenced in May that year. The Nagarjuna Construction Company (NCC), an Andhra Pradesh-based construction company is executing the construction work.

The first phase of the campus will have academic blocks, administrative blocks, auditorium, library and other buildings. There will be 17 buildings of G+3 height and around 50 classrooms will be built in the first phase, which will be completed by February 2020. Singh was also happy to note that an additional 100 acres will be allotted by the state government for commercial use to generate funds for the university.

Vice-chancellor Sunaina Singh also made a presentation to the members of the Finance Commission on the progress being made by the university not only on the construction front but also in introducing new academic roadmap, opening a new school of languages, reaching out to villages in the neighbourhood, administrative reforms, opening health centre for students and staff, norms for financial transparency and other steps being taken by the university administration.

Finance Commission chief offers Bihar some hope

Says will consider demand for more Central funds; no word on special status

The Hindu_02.10.2018_PIB,Patna

PRESS TRUST OF INDIA
PATNA

Finance Commission Chairman N.K. Singh on Monday said it would "sympathetically" consider the issue of regional inequality in the eastern region and the demand for increased share of Central funds to Bihar.

A team of the 15th Finance Commission, led by Mr. Singh, is on a three-day visit to Bihar.

"There is no question of looking into Bihar's case unsympathetically (on more share of Central funds)... I would assure you that the Commission would sympathetically consider regional inequality and eastern India inequality," he said.

The Finance Commission chief, however, did not make any comment on the call for according special category status to Bihar, raised by Assembly Speaker Vijay Kumar Choudhary.

Mr. Singh was speaking at a national seminar on 'Addressing the Problems of Inter-State and Inter-District Disparity in India' here.

Finance Commission Chairman N.K. Singh addresses a seminar in Patna on Monday. ▪ PTI

Referring to statements of Mr. Choudhary and Jharkhand Minister Saryu Rai in which they were critical of the functioning of the NITI Aayog, Mr. Singh said, "It would be completely inappropriate for the Finance Commission to comment on NITI Aayog. Commenting on NITI Aayog is beyond its domain."

Talking about centrally-sponsored schemes, the Finance Commission Chairman questioned the relevance of a high number of such programmes.

"You will be surprised to know the numbers of Central schemes. However, it remains to be seen whether all these schemes are required, they are serving their purpose, and also if the money allotted is necessary.

"The Shivraj Singh Chouhan Committee had rationalised the schemes but it did not have much impact... It is a huge responsibility bestowed upon us (the Commission) to evaluate these schemes," Mr. Singh said.

Devolution of funds

Mr. Choudhary, during his address at the seminar, also pitched for devolution of more funds from the commission to "backward" States like Bihar, which has "performed well with limited resources".

He also raised the issue of according special category status to Bihar as it is a "geographically unfortunate" State, "73% of whose area is flood-prone due to rivers originating from neighbouring Nepal."

Bihar's share in the Central divisible pool reduced to 9.6% in the 14th Finance Commission from 10.9%, owing to a formula adopted for horizontal distribution of resources.

Times of India_02.10.2018_PIB,Patna

Finance panel 'sympathetic' to Bihar

Commission Chairman Singh Admits State's Geographical Handicaps

Piyush.Tripathi
@timesgroup.com

Patna: Fifteenth Finance Commission chairman N K Singh has assured Bihar that the state's demands will be "sympathetically" considered by the commission, particularly because of its geographical constraints.

"There is no question of being unsympathetic to Bihar as we prepare to give Fifteenth FC's recommendations," Singh said while addressing at a seminar organised by the Asian Development Research Institute (ADRI) in Patna on Monday.

The FC chairman, who along with a team of the commission is on a three-day visit to the state, said the historical experiences of countries like Italy were very helpful in understanding the issues facing Bihar and other such states.

Several academics, business leaders, politicians, senior officials and members of the intelligentsia attended the daylong national seminar on 'Addressing the problems of inter-state and inter-district disparity of India", which was sponsored by the FC.

15th Finance Commission chairman N K Singh addresses a seminar organized by Asian Development Research Institute on Monday

Stating that the Terms of Reference of the Fifteenth FC followed the provisions contained in Article 280 of the Constitution, Singh said the commission's decision on the divisible pool of resources between the Centre and states would try to strike a balance between the provisions and the demands arising countrywide.

He also underlined the need to evaluate the numerous centrally sponsored schemes with an aim to bring efficiency and streamline their finances. "The issues that the Fifteenth FC has been finding to be 'very complex' have actually been found so even by the previous FCs," Singh said.

Earlier, Bihar assembly Speaker Vijay Kumar Chaudhary reiterated the Nitish Kumar government's long- pending demand for special state status to Bihar.

"I agree that granting special status is out of the purview of this FC, but your attention is required to provide the required thrust for the development of Bihar. If Bihar's geographical makeup (which is a top parameter for granting this status to any states) is considered, the state fits the bill for the first and foremost. Around 73% of the geographical expanse of the state are flood prone. Water from Nepal inundates north Bihar almost every year, due to which the state suffers a lot," Chaudhary said.

Taking a dig at Niti Aayog which replaced the Planning Commission, Chaudhary said, "Niti Aayog appears to be stuck with jugglery of words and academic forays. It should rather ensure that targets for development are not missed."

Chaudhary also emphasized the need to monitor the implementation of the Fifteenth FC recommendations.

Singh later said Chaudhary's worries truly reflected the wish of the people of the state. "It will be inappropriate for the FC to comment on Niti Aayog as it is beyond its domain," he said.

Earlier, ADRI's member-secretary Shaibal Gupta in his welcome address said the inter-state and inter-district development disparity was not an academic subject alone. "It is a serious development challenge and its reduction requires responses from various sources such as the central and state governments, national and international development agencies, academics, professionals, civil society organisations, media and others," he said.

The FC is a statutory body constituted every five years to devise a formula for allocation of central tax proceeds between the Centre and the states as well as among states and local bodies. The recommendations of the Fifteenth FC, which was constituted in November last, will come into effect from April 1, 2020.

htpatna

In search of fine balance, finance panel chief allays concerns on disparity

THRASHING IT OUT The 15th Finance Commission led by its chairman NK Singh will also deliberate with representatives of local bodies, political parties and representatives of trade and commerce

Arun Kumar
arunk@htlive.com

PATNA: Fifteenth Finance Commission chairman NK Singh on Monday assured that the panel would look into Bihar's concerns over its geographical disadvantage and regional disparity so that it could catch up with the developed states.

However, he cautioned that he needed to maintain a balance between central tax proceeds and demands by states.

He was delivering the inaugural address at a national seminar, 'Problems of inter-state and inter-district disparity of India', organised by the Asian Development Research Institute (ADRI). Singh's observations came after the Bihar legislative assembly speaker Vijay Kumar Choudhary, and the Jharkhand minister of parliamentary affairs, food and supply department, Saryu Rai, strongly batted for regional balance in fund allocation.

The commission will deliberate with representatives of local bodies, political parties and representatives of trade and commerce.

Singh said all finance commissions had grappled with the complex issues concerning Bihar's geographical limitations and regional disparity. "I remember former Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee once said with reference to Pakistan that you cannot change your neighbour. Similarly, Bihar cannot change its geography. It is a reality, though not its fault," he added.

However, he said, there was no question of being unsympathetic to Bihar in the 15th FC recommendations. "But FC has to strike a balance between the provisions and the demands across the country; reward performers and take steps to arrest regional disparity. Besides, it has a complex task at hand to evaluate the roles of the Centre and states," he added.

Singh also underlined the need to evaluate innumerable centrally-sponsored schemes to know if they were actually serving their purpose. "There are also central schemes. The concurrent list is also getting longer, with several new additions. These are complex issues before FC, and it cannot rush to any conclusion," he added.

He also dwelt on the vertical and horizontal devolution of funds, need to reward performers and incentivise states to help them catch up, issues concerning funding of the Panchayati Raj institutions, and the question of inter-district disparity even in the developed states.

Finance commission members, including chairman NK Singh, holding a meeting with officials, in Patna on Monday. SANTOSH/HT

He praised Vijay Kumar Choudhary for championing Bihar's cause and reflecting the state's sentiments and Rai for underlining regional disparity.

Choudhary, in his presidential address, said that Bihar qualified for a better deal from FC, based on its consistent high growth rate, and historical and geographical disadvantages. "This is the first FC since the implementation of GST. Bihar has to grapple with problems, which are not its own making. This was the reason why the state had demanded the special category status," he added.

Choudhary said complicated nomenclatures would not serve any purpose as assessment and monitoring remained neglected. "Bihar had 37 of the 38 districts covered under backward region grant fund (BRGF), but now there is a new concept of aspirational districts. How will it help Bihar? Jugglery of stats and change in names will not bring about any change," he asked.

Jharkhand minister Rai, in his special address, said though there had been improvement in all spheres, the gaps still remained. "Despite having abundant natural resources, many states in eastern India could not benefit in the desired way. What is important is proper implementation of policies. For this, FC should be given a permanent character," he added.

Welcoming the guests, ADRI's member-secretary Shaibal Gupta said the inter-state and inter-district development disparity was not an academic problem alone, but a development challenge. He sought help from "central and state governments, national and international development agencies, academicians, professionals, civil society organizations, and media", for an inclusive growth.

Sujata Chaturvedi, principal secretary of the Bihar finance department, outlined the major objectives of the seminar. ADRI's director Prabhat P Ghosh thanked all speakers and audience for their presence.

Finance Commission chairman NK Singh (left) **with Bihar Assembly Speaker Vijay Kumar Chaudhary and Jharkhand minister Saryu Roy at the ADRI seminar in Patna on Monday.** Picture by Nagendra Kumar Singh

Central scheme cut hint, balm for Bihar

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Patna: Finance Commission chairman N.K. Singh on Monday questioned the relevance of the high number of centrally sponsored schemes, and gave indications that many of them could be done away with.

"Does anyone know how many centrally sponsored schemes are running? Why are they running? Are benefits reaching the ground level? You will be surprised to know the numbers of central schemes. However, it remains to be seen whether all these schemes are required, are they serving their purpose, and also if the money allotted is necessary. The Shivraj Singh Chouhan Committee had rationalised the schemes but it did not have much impact... It is a huge responsibility bestowed upon us (the commission) to evaluate these schemes," Singh said while addressing a national seminar, "Addressing the problems of Inter-State and Inter-district disparity of India", at a city hotel.

The event was jointly organised by the Fifteenth Finance Commission and the Asian Development Research Institute.

Singh, a former Bihar cadre IAS officer who had served in key positions in government, including as revenue secretary, said the commission would "sympathetically" consider the issue of regional inequality in the eastern region and the demand for increased share of central funds to Bihar.

"There is no question of looking into Bihar's case unsympathetically (on more share of central funds)... I would assure you that the commission would sympathetically consider regional inequality and eastern India inequality...," Singh said.

The Finance Commission chief, however, did not comment on the call for according special category status to Bihar, raised by Bihar Assembly Speaker Vijay Kumar Chaudhary.

Referring to statements of Chaudhary and Jharkhand minister Saryu Roy in which they were critical of the functioning of the Niti Aayog, Singh said: "It would be completely inappropriate for the Finance Commission to comment on Niti Aayog. Commenting on Niti Aayog is beyond its domain."

Singh also hinted that the Commission would look into the aspect of funds to be allotted to panchayats and local bodies. "There is a list sent by the President of India on issues related to finance which is quite long. We will have to address those issues," he said.